Vol 8, Issue 11, 2025 **Impact Factor: 8.535** DOI: https://doi.org/10.31426/ijamsr.2025.8.11.8914

IJAMSR

**International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281**

# परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का बच्चों की विद्यालयीय भागीदारी पर प्रभाव: नालंदा जिला, बिहार का एक अध्ययन

**मुकेश कुमार सिंह**

शोधार्थी (पीएच.डी. – शिक्षा), शिक्षा विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय
साईं नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड, भारत.

**डॉ. पंकज कुमार यादव**

प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, मानविकी एवं सामाजिक विज्ञान संकाय
साईं नाथ विश्वविद्यालय, रांची, झारखंड, भारत.

## सार

प्रस्तुत शोध लेख बिहार राज्य के नालंदा जिले के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों में 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों की विद्यालयीय भागीदारी पर परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के प्रभाव का गहन विश्लेषण करता है। अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य यह समझना है कि पारिवारिक आय, माता-पिता की शैक्षिक स्थिति, आजीविका के साधन, भूमि स्वामित्व, आवासीय परिस्थिति तथा सामाजिक परिवेश जैसे कारक बच्चों के विद्यालय में नामांकन, नियमित उपस्थिति, शैक्षिक निरंतरता एवं विद्यालय त्याग (ड्रॉप-आउट) की प्रवृत्ति को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। अध्ययन के निष्कर्ष यह स्पष्ट करते हैं कि केवल विद्यालयों की भौतिक उपलब्धता अथवा शैक्षिक अवसंरचना का विस्तार बच्चों की प्रभावी विद्यालयीय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। जिन परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति कमजोर पाई गई, वहाँ बच्चों की अनियमित उपस्थिति एवं विद्यालय छोड़ने की संभावना अपेक्षाकृत अधिक देखी गई। इसके विपरीत, जिन परिवारों में माता-पिता, विशेषकर माता की शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत उच्च था, वहाँ बच्चों की विद्यालयीय निरंतरता अधिक मजबूत पाई गई। शोध यह भी दर्शाता है कि गरीबी, आजीविका की असुरक्षा तथा सामाजिक-आर्थिक विषमताएँ शिक्षा की सार्वभौमिकता के लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रमुख बाधा के रूप में कार्य करती हैं। इस प्रकार, अध्ययन शिक्षा नीतियों की जमीनी वास्तविकताओं को उजागर करते हुए यह संकेत करता है कि विद्यालयीय भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु शैक्षिक सुधारों के साथ-साथ परिवार-केंद्रित सामाजिक-आर्थिक हस्तक्षेपों की भी नितांत आवश्यकता है। यह शोध नीति-निर्माताओं, शैक्षिक योजनाकारों एवं शोधकर्ताओं के लिए ग्रामीण शिक्षा से जुड़े निर्णयों में एक महत्वपूर्ण संदर्भ प्रस्तुत करता है।

**मुख्य शब्द:** सामाजिक-आर्थिक स्थिति, विद्यालयीय भागीदारी, नामांकन, ग्रामीण शिक्षा, नालंदा

## भूमिका

भारत में शिक्षा को सामाजिक न्याय, समानता तथा समावेशी विकास का प्रमुख साधन माना गया है। शिक्षा न केवल व्यक्ति के बौद्धिक एवं नैतिक विकास में सहायक होती है, बल्कि सामाजिक गतिशीलता, आर्थिक सशक्तिकरण एवं लोकतांत्रिक मूल्यों के सुदृढ़ीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है (तिलक, 2007)। इसी दृष्टिकोण के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A के माध्यम से 6–14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान किया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार

IJAMSR

**International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281**

अधिनियम, 2009 द्वारा विधिक रूप से लागू किया गया (भारत सरकार, 2009)। हालाँकि, शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु किए गए इन संवैधानिक एवं नीतिगत प्रयासों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में बच्चों की विद्यालयीय भागीदारी आज भी एक गंभीर चुनौती बनी हुई है। नामांकन दर में वृद्धि के बावजूद विद्यालय में बच्चों की नियमित उपस्थिति, शैक्षिक निरंतरता तथा विद्यालय त्याग (ड्रॉप-आउट) की समस्या विशेष रूप से ग्रामीण समाज में स्पष्ट रूप से देखी जाती है (डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर एजुकेशन, 2017)। यह स्थिति इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि विद्यालयीय भागीदारी को केवल शैक्षिक अवसंरचना या विद्यालयों की उपलब्धता के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता, बल्कि इसके पीछे गहरे सामाजिक-आर्थिक कारक कार्यरत हैं (गोविन्दा, आर., एवं बंद्योपाध्याय, एम, 2011)। नालंदा जिला, जो ऐतिहासिक रूप से भारत की ज्ञान-परंपरा और शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा है, वर्तमान समय में भी सामाजिक-आर्थिक विषमताओं से अछूता नहीं है। यद्यपि जिले में विद्यालयों की संख्या तथा शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि हुई है, तथापि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आर्थिक असुरक्षा, माता-पिता की अशिक्षा, आजीविका के सीमित साधन, भूमि स्वामित्व की असमानता तथा सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताएँ बच्चों की विद्यालयीय भागीदारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2018)। परिणामस्वरूप, कई बच्चे प्रारंभिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर ही शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। पूर्ववर्ती अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि परिवार की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बच्चों की शिक्षा में निरंतरता का एक प्रमुख निर्धारक है। जिन परिवारों की आय कम होती है अथवा जिनकी आजीविका अस्थायी होती है, वहाँ बच्चों को शिक्षा के स्थान पर आर्थिक गतिविधियों में संलग्न कर दिया जाता है, जिससे विद्यालयीय भागीदारी प्रभावित होती है (द्रेज़, जे., एवं सेन, ए, 2013)। इसके अतिरिक्त, लैंगिक असमानता भी एक महत्वपूर्ण कारक है, जिसके कारण बालिकाओं की विद्यालयीय भागीदारी अपेक्षाकृत कम पाई जाती है (यूनेस्को, 2015)। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन नालंदा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और बच्चों की विद्यालयीय भागीदारी के बीच संबंधों का विश्लेषण करता है। यह शोध शिक्षा की सार्वभौमिकता से संबंधित नीतियों की जमीनी वास्तविकताओं को उजागर करने के साथ-साथ यह भी रेखांकित करता है कि शैक्षिक सुधारों के साथ-साथ सामाजिक-आर्थिक हस्तक्षेपों की भी नितांत आवश्यकता है। अध्ययन से प्राप्त निष्कर्ष नीति-निर्माताओं, शैक्षिक योजनाकारों तथा शोधकर्ताओं को ग्रामीण शिक्षा से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु व्यावहारिक दिशा प्रदान करते हैं।

## अध्ययन के उद्देश्य

1. परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का बच्चों के विद्यालय नामांकन पर प्रभाव का अध्ययन करना।
2. आय, अभिभावकों की शिक्षा एवं पेशे का विद्यालयीय उपस्थिति पर प्रभाव विश्लेषित करना।
3. विद्यालय छोड़ने (Drop-out) के प्रमुख सामाजिक-आर्थिक कारणों की पहचान करना।

## शोध पद्धति

- प्रस्तुत अध्ययन परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति का बच्चों के विद्यालय नामांकन, नियमित उपस्थिति तथा विद्यालय त्याग पर प्रभाव का विश्लेषण करने हेतु वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध अभिकल्प पर आधारित है। इस शोध अभिकल्प का चयन इसलिए किया गया ताकि एक ओर ग्रामीण

IJAMSR

**International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281**

क्षेत्रों में बच्चों की विद्यालयीय भागीदारी की वर्तमान स्थिति का तथ्यात्मक वर्णन किया जा सके तथा दूसरी ओर विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारकों और शैक्षिक परिणामों के बीच संबंधों का गहन विश्लेषण किया जा सके।

- अध्ययन के लिए नालंदा जिले के चयनित ग्रामीण गाँवों को शोध क्षेत्र के रूप में चुना गया, जिससे ग्रामीण सामाजिक संरचना और आर्थिक परिस्थितियों का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया जा सके। नमूना चयन में प्रतिनिधिकता का विशेष ध्यान रखा गया, ताकि विभिन्न आय वर्गों, जातीय समूहों एवं सामाजिक पृष्ठभूमि से संबंधित परिवारों को अध्ययन में सम्मिलित किया जा सके।
- आँकड़ों के संग्रहण हेतु प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया। प्राथमिक आँकड़े संरचित प्रश्नावली एवं साक्षात्कार विधि के माध्यम से संकलित किए गए, जिनमें बच्चों के अभिभावकों से पारिवारिक आय, माता-पिता की शिक्षा, पेशा, आजीविका के साधन, बच्चों की विद्यालयीय स्थिति तथा विद्यालय छोड़ने के कारणों से संबंधित जानकारी प्राप्त की गई। इसके साथ ही, विद्यालयों एवं शैक्षिक संस्थानों से संबंधित द्वितीयक आँकड़े सरकारी रिपोर्टों, जनगणना विवरणों एवं शैक्षिक अभिलेखों से एकत्र किए गए, जिससे अध्ययन को व्यापक संदर्भ प्रदान किया जा सके।
- संकलित आँकड़ों के विश्लेषण के लिए प्रतिशत विधि, तुलनात्मक विश्लेषण तथा सारणीबद्ध प्रस्तुति का प्रयोग किया गया। प्रतिशत विश्लेषण के माध्यम से विद्यालय नामांकन, उपस्थिति एवं ड्रॉप-आउट से संबंधित प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया गया, जबकि तुलनात्मक विश्लेषण द्वारा आय स्तर, अभिभावकों की शिक्षा एवं पेशे के संदर्भ में बच्चों की विद्यालयीय भागीदारी में विद्यमान अंतर का अध्ययन किया गया। इस प्रकार अपनाई गई शोध पद्धति ने अध्ययन के उद्देश्यों की प्रभावी पूर्ति करते हुए परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और बच्चों की शिक्षा के बीच संबंधों को स्पष्ट एवं व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत किया है।

## परिणाम एवं चर्चा

प्रस्तुत अध्ययन के परिणाम यह स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि निम्न आय वर्ग एवं भूमिहीन परिवारों से संबंधित बच्चों में विद्यालयीय अनियमितता तथा ड्रॉप-आउट की दर अपेक्षाकृत अधिक पाई गई। आँकड़ों की व्याख्या से यह ज्ञात होता है कि आर्थिक असुरक्षा और सीमित आय संसाधनों के कारण इन परिवारों में बच्चों को कम उम्र से ही कृषि कार्य, घरेलू श्रम अथवा दैनिक मजदूरी में संलग्न कर दिया जाता है, जिससे उनकी नियमित विद्यालय उपस्थिति बाधित होती है। (ग्राफ 1)

IJAMSR

**International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281**

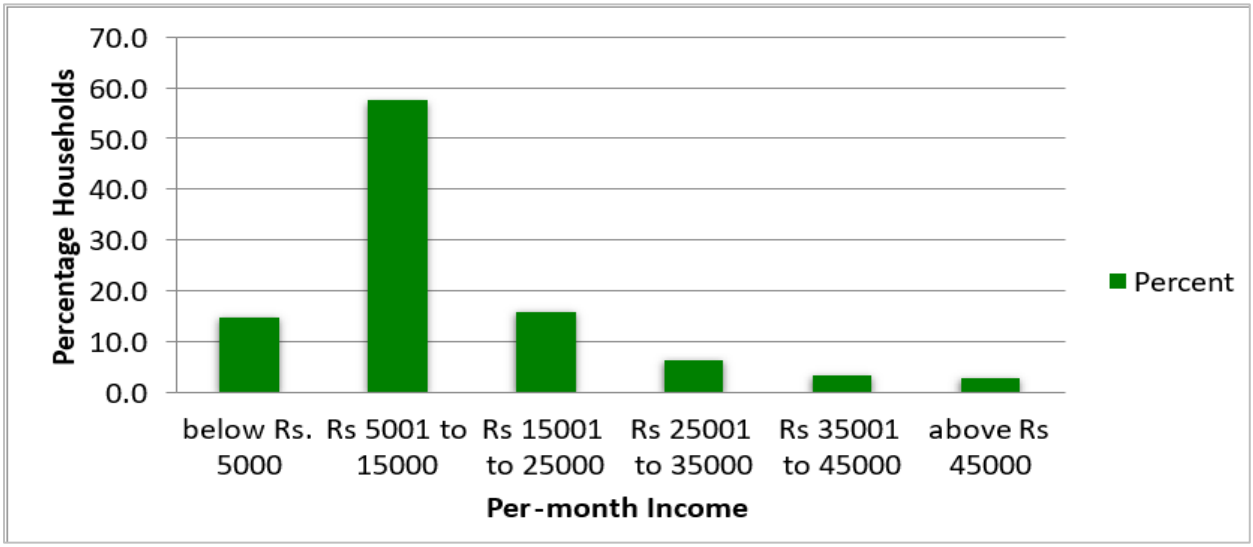


ग्राफ 1. आय के अनुसार परिवारों का प्रतिशत वितरण स्रोतः शोधकर्ता द्वारा एकत्रित डेटा

यह प्रवृत्ति उन परिवारों में अधिक स्पष्ट रूप से देखी गई, जहाँ आजीविका के स्रोत अस्थायी एवं अनियमित हैं। यह निष्कर्ष पूर्ववर्ती अध्ययनों के अनुरूप है, जिनमें यह प्रतिपादित किया गया है कि गरीबी बच्चों की शिक्षा में निरंतरता की सबसे बड़ी बाधा है (द्रेज़, जे., एवं सेन, ए, 2013; गोविन्दा, आर., एवं बंद्योपाध्याय, एम, 2011)। अध्ययन से यह भी स्पष्ट हुआ कि अभिभावकों की शिक्षा, विशेष रूप से माता की शिक्षा, बच्चों की विद्यालयीय निरंतरता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिन परिवारों में माता-पिता, विशेषकर माताएँ, साक्षर अथवा शिक्षित पाई गईं, वहाँ बच्चों की नियमित उपस्थिति, कक्षा उत्तीर्णता तथा विद्यालय में बने रहने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक देखी गई (तालिका 1)।

तालिका 1. परिवार के सदस्यों का शैक्षिक स्तर

| शैक्षणिक स्तर | घर का मुखिया | माँ | पिता |
|---|---|---|---|
| निरक्षर/ कभी स्कूल नहीं गए | 16.3 | 31.6 | 6.8 |
| स्कूली शिक्षा के बिना साक्षर | 5.8 | 5.8 | 4.2 |
| प्राथमिक स्तर | 8.4 | 9.5 | 9.5 |
| उच्च प्राथमिक स्तर | 27.9 | 28.4 | 31.1 |
| माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर | 35.8 | 19.5 | 39.5 |
| स्नातक/स्नातकोत्तर | 5.8 | 5.3 | 7.9 |
| खत्म हो चुका | -- | -- | 1.1 |
| कुल | 100 | 100 | 100 |

IJAMSR

**International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281**

आँकड़ों की व्याख्या से यह संकेत मिलता है कि शिक्षित माताएँ बच्चों की शिक्षा के महत्व को अधिक समझती हैं तथा उन्हें विद्यालय भेजने एवं शिक्षा जारी रखने हेतु प्रेरित करती हैं। यह निष्कर्ष राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय अध्ययनों से भी समर्थित है, जिनमें माता की शिक्षा को बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि का एक निर्णायक कारक माना गया है (तिलक, 2007; यूनेस्को, 2015)। इसके अतिरिक्त, अध्ययन के परिणाम यह भी दर्शाते हैं कि विद्यालय की भौगोलिक दूरी एवं परिवहन सुविधाओं का अभाव विद्यालय छोड़ने का एक प्रमुख कारण है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय घर से अधिक दूरी पर स्थित हैं अथवा जहाँ सुरक्षित एवं सुलभ परिवहन साधन उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ बच्चों की अनियमित उपस्थिति तथा ड्रॉप-आउट की संभावना अधिक पाई गई। यह समस्या विशेष रूप से बालिकाओं के संदर्भ में अधिक गंभीर रूप में सामने आई, जहाँ सुरक्षा संबंधी चिंताएँ भी विद्यालय त्याग को बढ़ावा देती हैं। पूर्ववर्ती शोधों में भी विद्यालय दूरी को ड्रॉप-आउट का एक महत्वपूर्ण निर्धारक माना गया है (मानव संसाधन विकास मंत्रालय, 2018; डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर एजुकेशन, 2017)। कुल मिलाकर, अध्ययन के परिणाम यह संकेत करते हैं कि विद्यालयीय उपस्थिति एवं निरंतरता केवल विद्यालयों की संख्या अथवा शैक्षिक अवसंरचना पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, अभिभावकों की शिक्षा तथा भौगोलिक परिस्थितियों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है (ग्राफ 2)।

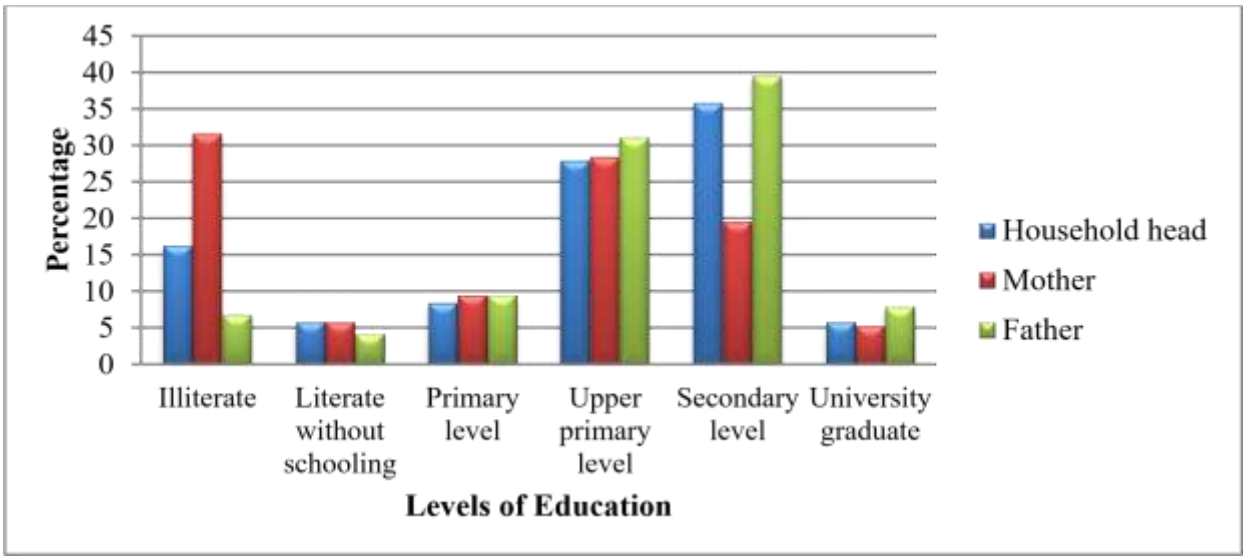


ग्राफ 2. शिक्षा के स्तर के अनुसार घरों में सदस्यों का प्रतिशत वितरण स्रोतः शोधकर्ता द्वारा एकत्रित डेटा

अतः विद्यालय त्याग की समस्या को कम करने हेतु ऐसी नीतियों की आवश्यकता है, जो शिक्षा के साथ-साथ परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार एवं बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता पर भी केंद्रित हों।

## निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के समग्र विश्लेषण के आधार पर यह निष्कर्ष स्पष्ट रूप से निकाला जा सकता है कि बच्चों की विद्यालयीय भागीदारी को बढ़ाने हेतु केवल शैक्षणिक ढाँचे का विस्तार अथवा विद्यालयों की भौतिक उपलब्धता सुनिश्चित करना पर्याप्त नहीं है। यद्यपि विद्यालयों की संख्या में वृद्धि एवं शैक्षिक सुविधाओं का विकास आवश्यक है, तथापि यह बच्चों की नियमित उपस्थिति, शैक्षिक निरंतरता तथा विद्यालय में बने रहने की गारंटी नहीं देता। अध्ययन से यह प्रमाणित होता है कि परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति बच्चों की शिक्षा में

IJAMSR

**International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281**

निर्णायक भूमिका निभाती है। निम्न आय वर्ग, भूमिहीनता, आजीविका की असुरक्षा तथा अभिभावकों की अशिक्षा जैसी परिस्थितियाँ बच्चों की विद्यालयीय भागीदारी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती हैं। ऐसे परिवारों में आर्थिक दबाव के कारण बच्चों को शिक्षा के स्थान पर श्रम गतिविधियों में संलग्न कर दिया जाता है, जिससे उनकी शैक्षिक प्रगति बाधित होती है। इसके अतिरिक्त, अभिभावकों में शिक्षा के दीर्घकालिक लाभों के प्रति जागरूकता का अभाव भी बच्चों की विद्यालयीय निरंतरता में एक महत्वपूर्ण बाधा के रूप में उभरकर सामने आता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि विद्यालयीय भागीदारी को सुदृढ़ करने हेतु परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार को शिक्षा नीतियों का अभिन्न अंग बनाया जाए। इसके साथ ही, अभिभावक जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा के महत्व, विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित किया जाना चाहिए। साथ-साथ लक्षित सरकारी हस्तक्षेप, जैसे आर्थिक सहायता योजनाएँ, छात्रवृत्तियाँ, पोषण एवं परिवहन सुविधाएँ तथा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम, ग्रामीण एवं वंचित वर्गों तक प्रभावी रूप से पहुँचाए जाने की आवश्यकता है। समग्र रूप से यह अध्ययन इस तथ्य को रेखांकित करता है कि विद्यालयीय भागीदारी में वृद्धि एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जिसके लिए शिक्षा व्यवस्था, परिवार, समुदाय तथा राज्य के बीच समन्वित प्रयास अनिवार्य हैं। यदि शैक्षिक सुधारों को सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ समेकित रूप से लागू किया जाए, तो सार्वभौमिक, समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लक्ष्य को वास्तविक रूप में प्राप्त किया जा सकता है।

## संदर्भ

प्रस्तुत अध्ययन लेखक की पीएच.डी. थीसिस पर आधारित है

**आभार - प्रकटन**

लेखक इस शोध पत्र के सफल संपादन में सहयोग प्रदान करने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता है। विशेष रूप से लेखक अपने शोध निर्देशक डॉ. पंकज कुमार यादव, प्राध्यापक, शिक्षा विभाग, साईं नाथ विश्वविद्यालय, रांची के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता है, जिनके मार्गदर्शन, विद्वतापूर्ण सुझावों एवं सतत प्रेरणा से यह शोध कार्य संभव हो सका। लेखक साईं नाथ विश्वविद्यालय, रांची के शिक्षा विभाग एवं पुस्तकालय के प्रति भी आभारी है, जिन्होंने शोध से संबंधित आवश्यक शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराए। साथ ही, नालंदा जिले के चयनित ग्रामीण क्षेत्रों के अभिभावकों, छात्रों एवं शिक्षकों का धन्यवाद करता है, जिन्होंने अध्ययन के दौरान आवश्यक जानकारी एवं सहयोग प्रदान किया।

**Copyright:** © 2025 लेखक। यह शोध लेख मौलिक है तथा इसे पूर्व में किसी अन्य पत्रिका में प्रकाशित नहीं किया गया है।

## संदर्भ सूची

- डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम फ़ॉर एजुकेशन (DISE). (2017). भारत में स्कूली शिक्षा: सांख्यिकी एवं संकेतक. नई दिल्ली, भारत: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्थान (NIEPA)।
- द्रेज़, जे., एवं सेन, ए. (2013). एन अनसर्टेन ग्लोरी: इंडिया एंड इट्स कॉन्ट्राडिक्शन्स. नई दिल्ली, भारत: पेंगुइन बुक्स।

IJAMSR

**International Journal of Advanced Multidisciplinary Scientific Research (IJAMSR) ISSN:2581-4281**


- गोविन्दा, आर., एवं बंद्योपाध्याय, एम. (2011). भारत में प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच: देशीय विश्लेषणात्मक समीक्षा. नई दिल्ली, भारत: राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (NUEPA)।
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD). (2018). शिक्षा संबंधी सांख्यिकी: एक दृष्टि. नई दिल्ली, भारत: भारत सरकार।
- तिलक, जे. बी. जी. (2007). शिक्षा, असमानता और विकास. नई दिल्ली, भारत: रावत पब्लिकेशन्स।
- यूनेस्को. (2015). सभी के लिए शिक्षा 2000–2015: उपलब्धियाँ और चुनौतियाँ. पेरिस, फ्रांस: यूनेस्को पब्लिशिंग।